दिल्ली में सीमेन्ट की कमी

2404. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली मे सीमेट की भारी कमी है तथा यह काले बाजार से 50 रु.ये प्रति बोरी की दर से बिक रही है, और

(ख) यदि हा, तो गत दो वर्षों से लगातार कमी क्यो है और सरकार इस बारे मे क्या प्रबन्ध कर रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) उत्पादन सम्बन्धी विभिन्न बाधाओ, जैसे बिजली की कटौती कोयला तथा बन्द वैगनो आदि की अपर्याप्त उपलब्धि, जो उद्योग के नियन्त्रण से बाहर है, के परिणामस्वरूप इस समय उपलब्ध सीमेन्ट की माग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नही है। अत दिल्ली मे सीमेन्ट की कमी, देश भर मे सीमेन्ट की समग्र रूप से व्याप्त कमी का एक भाग है। सरकार द्वारा नियत मूल्य स्तर से अधिक जिस भाव पर दिल्ली मे सीमेन्ट बेची जाता है इसके बारे मे सरकार को कोई विशिष्ट जानकारी नही है, और यह असम्भावित नही है कि कुछ असामाजिक तत्व स्थिति का नाजायज लाभ उठा रहे हो।

सरकार द्वारा नियत मूल्य पर सीमेन्ट उपलब्ध कराने के विचार से, सभी राज्य सरकारो को परमिट/लाइसेन्स दे कर सीमेन्ट की बिक्री का नियमन करने के बारे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन आदेश जारी करने के लिए कहा गया था। दिल्ली प्रशासन ने भी ऐसा आदेश जारी कर दिया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन, दिल्ली प्रशासन को अनैतिक व्यवहार करने वाले असमाजिक तत्वो के साथ निपटने के लिए उपयुक्त अधिकार प्राप्त है।

सीमेन्ट की उपलब्ध मात्रा का समान रूप से वितरण करने हेतु प्रत्येक राज्य के लिए उनके पिछले पांच वर्षों की औसत खपत के आधार पर 1 जुलाई, 1973 से 30 जून, 1974 तक की अवधि के लिए कोटे निर्धारित किये गये थे। ये कोटे केन्द्रीय सरकार के निर्माण कार्यों और बडे-बडे मध्यम उद्योगो की आवश्यकताओ के अलावा है जिन्हे केन्द्र द्वारा अलग से पूरा किया जाता है। आगामी तिमाही की अवधि मे कारखानो से सीमेन्ट की सम्भावित उपलब्धि के आधार पर प्रत्येक तिमाही के लिए आवटन किया जाता है।

सीमेन्ट की उपलब्ध मात्रा के वितरण मे सुधार करने के विचार से रेल द्वारा सीमेन्ट ले जाने की व्यवस्था की नियमित समीक्षा सचिवो की एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा की जाती है ताकि कारखानो की सीमेन्ट लाने ले जाने सम्बन्धी कठिनाइयो से तथा सभव सहायता की जा सके। खान और धातु विभाग के अन्तर्गत एक स्थायी सम्पर्क (लिंकेज) समिति का गठन किया गया है तथा विभिन्न सीमेन्ट कारखानो को उनकी कोयले की आवश्यकता मालूम करने के पश्चात् भिन्न-भिन्न कोयला खानो से सम्बन्द्ध कर दिया गया है। सीमेन्ट के विभिन्न कारखानो को कोयला सप्लाई करने की स्थिति की प्रत्येक 10वे दिन समीक्षा करने के लिए कलकत्ता मे एक 'मानीटरिंग' प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। 170 00 लाख मी० टन की अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेन्स/आशयपत्र भी जारी किए जा चुके है जिसमे से 1974-75 मे लगभग 17 लाख मी० टन की क्षमता पूरी हो जाने की सम्भावना है।

ट्रैक्टरो के डायरों की कमी

2405. **डा लक्ष्मीनारायण पांडेय :**
श्री चन्द्रशेखर सिंह :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को निर्धारित दर

पर ट्रैक्टर न मिलने के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है जिसका प्रभाव सीधे उत्पादन पर पड रहा है, और

(ख) यदि हां तो किसानों को नियन्त्रित दर पर ट्रैक्टरों के टायर उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) :

(क) ट्रैक्टर के टायरों के मूल्य पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Annual target achieved by National Projects Construction Corporation Limited

2406 SHRI ARVIND M PATEL
SHRI D P JADEJA

Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state

(a) whether the National Projects Construction Corporation Limited has drawn up a programme to achieve an annual target of Rs 8 to 10 crores, and

(b) if so, the concrete steps taken to achieve the target set out?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) (a) The National Projects construction Corporation Ltd has drawn a programme to achieve a target of executing works of the value of Rs 871 07 lakhs during 1974-75,

(b) Steps taken by the Corporation to achieve this target *inter-alia* include

(i) fixing targets for the execution of works by individual units of the Corporation,

(ii) advance planning for furnishing resources of men and machinery for each unit to enable it to achieve the target set for it,

(iii) weekly review of the progress of work;

(iv) a monthly review of the targets fixed for each unit with a view to take corrective measures as required, and

(v) payment of incentive bonus to the employees of the units which achieve the targets fixed for them

Raid on office premises and residences of officers of Birla Concern

2407 SHRI RAGHUNANDAN LAL BHATIA
SHRI SHRIKISHAN MODI

Will the PRIME MINISTER be pleased to state

(a) whether the Enforcement Directorate had raided office premises of Birla concern and residences of their officers in the 1st week of May 1974 and

(b) whether seized documents reveal hidden sources of income of this group?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) (a) No search of the office premises of any Birla concern or the residences of the officers of any Birla concern, has been carried out by the Enforcement Directorate during May 1974

(b) Does not arise

Effect of Low Melting of Snow in Himalayan Ranges on the flow of Water in Northern Rivers and in Power Generation in Bhakra

2408 SHRI RAGHUNANDAN LAL BHATIA
SHRI D D DESAI

Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state

(a) whether there has been low melting of snow in the recent years